



आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan
रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952-2441142 Email: ce,appealsrajkot@gmail.com



सत्यमेव जयते

रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा :-

क	अपील फाइल संख्या Appeal File No.	मूल आदेश सं / OIO No.	दिनांक / Date
	V2/27,28,29/GDM/2017	ST/557,558,556/2016-17	12.01.2017

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-100-TO-102-2017-18

आदेश का दिनांक / Date of Order:	06.11.2017	जारी करने की तारीख / Date of issue:	09.11.2017
------------------------------------	-------------------	--	-------------------

**कुमार संतोष, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /
Passed by Shri Kumar Santosh, Commissioner (Appeals), Rajkot**

ग अपर आयुक्त/ समूह आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गान्धीधाम। द्वारा उपरोक्तित जारी मूल आदेश से जुड़ित।

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax Rajkot / Jamnagar / Gandhidham

घ **अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-**
M/s. Rankers International P. Ltd., "Rankers House" Plot No.12, Sector No. 1, Gandhidham-Kutch

इस आदेश(अपील) से व्यक्ति/कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में अपील कर सकते हैं।
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील विभागाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अन्तर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अन्तर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है।

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) विशेष बेंच/संयोजित बेंच/संयोजित बेंच सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील विभागाधिकरण की विशेष बेंच, ईस्ट ब्लॉक नं. 2, आर.के. पुरम, नए दिल्ली, का की जाती चाहिए।

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi is all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद (i) में बतलाया अपील के अलावा शेष सभी अपील सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील विभागाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय बेंच, द्वितीय तल, बहामल भवन असावा अहमदाबाद-380016 को की जाती चाहिए।

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2nd Floor, Bhaumal Bhawan, Asawa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(i) above

(iii) अपील विभागाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमवली, 2001, के नियम 6 के अन्तर्गत निर्धारित फॉर्म एफ-3 की धारा पहिली में दर्जे किया जाना चाहिए। इसमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की राशि हजार की राशि और लगाया गया जुर्माना, स्या 5 लाख या उससे कम, 5 लाख स्या 50 लाख तक अथवा 50 लाख स्या 100 लाख से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का अग्रदान संबंधित अपील विभागाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के साथ में किंवा श्री सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेडिफिक बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का अग्रदान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपील विभागाधिकरण की शाखा स्थित है। अग्रदान आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए आदेश-पर के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(B) अपील विभागाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अन्तर्गत सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित फॉर्म S.T-5 में धारा पहिली में की जा सकती है। इसमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की राशि हजार की राशि और लगाया गया जुर्माना, स्या 5 लाख या उससे कम, 5 लाख स्या 50 लाख तक अथवा 50 लाख स्या 100 लाख से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये अथवा 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का अग्रदान संबंधित अपील विभागाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के साथ में किंवा श्री सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेडिफिक बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का अग्रदान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपील विभागाधिकरण की शाखा स्थित है। अग्रदान आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए आदेश-पर के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- where the amount of service tax & interest/demand & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the Bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

(i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दायें की नवी जमाएं, सेवाएं नियमवली, 1994 के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रार 5.1-7 में की जा सकती एवं उसके साथ अप्रत्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा अधुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दशा का प्रति अर्पण की पंजीयन कर (जिसमें से एक प्रति प्रमाणिता होती रहित) और अधुक्त द्वारा सहायक अधुक्त अथवा उपधुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवाएं, को अंतीय न्यायपरिकाण को आकर्षण दने कराते वा धिटीय दने जाने अर्पण की प्रति भी साथ में समझ करनी होगी । /
The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST 7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाएं अधीनीय परीकरण (संसेट) के प्रति अपील के अंतर्गत में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35(२) के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाएं को भी लागू की गई है, इस अर्पण के प्रति अधीनीय परीकरण में अपील कराते समय उत्पाद शुल्क/सेवा का मांन के 10 प्रतिशत (10%) जब मांन एवं जुर्माने विकारित है, वा जुर्माना, जब केवल जुर्माने विकारित है, वा शुभलान किया जाए, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत जसा कि उजे वापी अधिनियम दय ररिठ दय बरुई बरा से अधिका न हो।
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाएं के अंतर्गत 'दाय विण वा शुल्क' में निम्न शामिल है:
(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेन्वेट जमा की गई नहीं जाय रहित
(iii) सेन्वेट जमा नियमवली के नियम 6 के अंतर्गत दय रकम
- बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के अंतर्गत से पूरे किती अधीनीय परीकरणों के समय वित्तीय नियम अउरी एवं अधीन को लागू नहीं होगी।

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 53 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.

Under Central Excise and Service Tax 'Duty Demanded' shall include :

- (i) amount determined under Section 11 D;
 - (ii) amount of erroneous Central Credit taken;
 - (iii) amount payable under Rule 6 of the Central Credit Rules.
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014

(C) भारत सरकार की पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India;
इस अर्पण की पुनरीक्षण परीका मिन्सिटीवित्त अशासि में, केडीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम परतुक के अंतर्गत अरर जयित, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त अशासि राज्य विक्ति, लोपी अडिन, जयन दय अवन, संसेट मांन, नई दिल्ही-110001, को किया जसा बाहिना । /
A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- (i) यदि मांन के किमी अकसल के अंतर्गत में, जहा अकसल किमी मांन को किमी कारखाने में अंतर गृह के परतजन के दौख वा किमी अन्म कारखाने वा फिर किमी एक अशर गृह से दुन्ने अशर गृह कारखाने के दौख, वा किमी अशर गृह में वा अशरने में मांन के परतन्करण के दौख, किमी कारखाने वा किमी अशर गृह में मांन के नुकसल के अंतर्गत में। /
In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
- (ii) भारत के बाहर किमी लघु वा अंग को निर्यत कर रहे मांन के विनिर्माण में प्रवृत्त कयो मांन पर अरी नद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (विसेट) के अंतर्गत में, जो भारत के बाहर किमी लघु वा अंग को निर्यत की गयी है। /
In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.
- (iii) यदि उत्पाद शुल्क वा शुभलान विण किता भारत के बाहर, नेपाल वा भूटान को मांन निर्यत किया गया है। /
In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- (iv) मुनिरियत उत्पाद के उत्पादन शुल्क के अंतर्गत के विण जो सूटी अरुई इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न धारावली के तहत मांन की गई है और दूने अर्पण जो अधुक्त (अपीन) के दयवा वित्त अधिनियम (सं. 2), 1998 की धारा 109 के दयवा निर्यत की गई लघुत अथवा समायोधि पर वा बाद में पारित किए गए है। /
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No 2) Act, 1998.
- (v) उपरोक्त आवेदन की दो परिया प्रथम अथवा EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपीन) नियमवली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस अर्पण के संक्षेप के 3 मांन के अंतर्गत की जानी रहित । उपरोक्त आवेदन के साथ मूल अर्पण वा अधीन अर्पण की दो परिया समझ की जानी रहित। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अंयवापी के साथ, के अंग पर TR-6 की प्रति समझ की जानी रहित। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OAO and Order-in-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Chalan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ मिन्सिटीवित्त निर्धारित शुल्क की अंयवापी की जानी रहित । /
जहाँ समझ रकम एक लाक अरुई वा उअरी रकम है जे अरुई 200/- का शुभलान किया जाए और यदि समझ रकम एक लाक अरुई से जयादा हो जे अरुई 1000/- का शुभलान किया जाए । /
The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- when the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

(D) यदि इस अर्पण में कई मूल अर्पणों का समावेश है तो प्रत्येक मूल अर्पण के लिए शुल्क का शुभलान, उपरोक्त दूने में किया जाना बाहिना। इस लघु के अंगे हय भी की निर्यत परी कराते में अरुई के लिए धारास्थिति अधीनीय अधिनियम की एक अपील वा केडीय अशर को एक अर्पण किता जता है । /
In case if the order covers various numbers of order in Original fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scribbles work if exciting Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each

(E) वहावर्षीय अंयवालय शुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसूची-1 के अंयवालय अंग अर्पण एवं समझ अर्पण की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क विक्रि ररिठ होना बाहिना । /
One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended

(F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाएं अधीनीय अधिनियम (संघे विधि) नियमवली, 1982 में धरिण एवं अंय संघिनित मांनरी को सम्मिन्ति करने जाने नियमों की और भी धयव अर्पण किया जता है । /
Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(G) उच्च अधीनीय परीकरणों को अधीन अधिनियम करने में सहायक 'सेवाएं' विक्तियों और अधिनियम धारावली के लिए, अधीनीय वित्तीय वेबसाइट www.cbec.gov.in की दय समझें है । /
For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in



:: ORDER IN APPEAL ::

The appeals listed herein below have been filed by M/s. Rankers International P. Ltd, "Ranker House", Plot No. 12, Sector No. 1, Gandhidham -Kutch (hereinafter referred to as "Appellant") against Orders-In-Original shown against each appeal no. (hereinafter referred to as "impugned orders") passed by the Assistant Commissioner, Service Tax Division, Gandhidham-Kutch (hereinafter referred to as "the lower adjudicating authority").

Sr. No.	Appeal File No.	Order-In-Original No. & Date	Period of Refund claim	Amount of refund claim rejected (in Rs.)
01.	V2/27/GDM /2017	ST/557/2016-17 12.01.2017	April & May, 2016	87,196/-
02	V2/28/GDM /2017	ST/558/2016-17 12.01.2017	October, 2016	67,448/-
03	V2/29/GDM/2017	ST/556/2016-17 12.01.2017	July to September, 2016	1,46,146/-

2. Since the issue involved is identical, all these appeals are being taken up together for decision.

3. The facts of the case are that the appellant filed refund claims under Notification No.41/2012-ST dated 29.06.2012 of service tax paid to various service providers for rendering taxable services in relation to export of goods for the period specified in the refund claims. The lower adjudicating authority vide impugned order rejected the refund claim for the amount as shown in the above Table.

4. Being aggrieved with the impugned orders, the appellant preferred the appeals, *inter-alia*, on the grounds that the lower adjudicating authority has erred in law and also on facts in rejecting the refund of Swachh Bharat Cess (hereinafter referred to as "SBC") and Krishi Kalyan Cess (hereinafter referred to as "KKC") without assigning any cogent reason thereof. The refund claims of SBC and KKC have been rejected without affording any opportunity to the appellant to explain their case and thus violating the principles of natural justice.

5. Personal hearing in the matter was attended to by Shri Abhishek Doshi, Chartered Accountant, who reiterated grounds of Appeal and submitted that they have not been given any SCN or even PH notice and orders have been issued without offering them any opportunities to explain their case; that SBC and KKC are to be treated like Service Tax and refund under Notification 41/2012-ST should be allowed to them; that SBC and KKC already granted earlier can't be recovered without issuance of SCN and without filing appeal against that order; that orders



passed are patently illegal and high handed; that orders should be set aside and appeals allowed as per written submissions made by them.

5.1 The written submission dated 02.11.2017 contained, inter-alia, following grounds:

- (i) Out of Refund claims of Service Tax paid on services utilized for export of goods under Notification No. 41/2012 dated 29.06.2012, amount of SBC and KKC involved was rejected on the ground that no clarification in respect of SBC and KKC has been issued.
- (ii) The refund of SBC and KKC granted earlier cannot be recovered directly from current claims without issuing SCN or PH notice, if earlier orders were erroneous, the department should have filed appeal against such orders.
- (iii) SBC and KKC are not separate tax in itself but Cess levied on transaction along with Service Tax, being levied from November, 2015 and June, 2016 respectively. Prior to that there was Education Cess and Secondary Education Cess and Refund claims submitted by appellant have been sanctioned for Service Tax along with education cess and secondary education cess. OIOs, sanctioning refund of SBC and KKC have not been appealed against and accepted by the department then each granted SBC and KKC can't be recovered without filing appeal. There are numbers of judgments which provide that cess are part of tax only and same cannot be separated from tax.
- (iv) The refund claims of appellant for December, 2015 and March, 2016 have been sanctioned after allowing SBC along with Service Tax and no further appeals preferred by the department against such OIOs.

Printed

FINDINGS:

6. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned orders, appeal memorandums and the submissions of the appellant. The issue to be decided in the present case is as to (i) whether the appellant is entitled for refund of SBC and KKC paid on services used for export of goods under Notification No. 41/2012-ST dated 29.06.2012 or not and (ii) whether earlier granted refund of SBC and KKC can be recovered without issuance of SCN or not.



31

7. The appellant has contended that the refund claims were rejected without assigning any cogent reasons, without issuance of SCN and without affording any opportunity to the appellant to explain their case and thereby the impugned orders have violated the principles of natural justice. I find force in the arguments made by the appellant. I find that the refund claims were decided by the lower adjudicating authority without issuance of SCN and even without granting opportunities of personal hearing to the appellant. It is settled position of law that the refund claims should not be rejected without issuance of SCN demonstrating reasons for denial of refund claims and without affording sufficient opportunities to explain their case. Hence, I find that the impugned orders are not sustainable at all, the same being non-speaking orders as far as rejecting refund claims of SBC and KKC is concerned.

7.1 I also find that the earlier granted refund of SBC and KKC can't be recovered without following due procedure of law and giving fair and sufficient opportunity to the appellant to explain the case.

8 In view of above facts, I am of the considered view that the impugned orders need to be set aside and the matter needs to be remanded back to the lower adjudicating authority to pass speaking and reasoned orders offering fair opportunities to the appellant.

8.1 I find that the Commissioner (Appeals) has power to remand appeals as decided by the Hon'ble CESTAT in the case of CCE, Meerut Vs. Singh Alloys (P) Ltd. reported as 2012(284) ELT 97 (Tri-Del). I also rely upon decision of the Hon'ble CESTAT in the case of CCE, Meerut-II Vs. Honda Seil Power Products Ltd. reported in 2013 (287) ELT 353 (Tri-Del) wherein it has been held that Commissioner (Appeals) has inherent power to remand a case under the provisions of Section 35A of the Act. The Hon'ble Gujarat High Court in Tax Appeal No. 276 of 2014 in respect of Associated Hotels Ltd. has also held that even after the amendment w.e.f. 11.05.2011 in Section 35A (3) of the Central Excise Act, 1944, the Commissioner (Appeals) would retain the power to remand.


9. In view of above, I set aside the impugned orders to the extent of rejection of refund of SBC & KKC and also for recovery of earlier granted SBC & KKC and allow the appeals by way of remand with direction to the appellant to submit their written submissions to the jurisdictional adjudicating authority within two months of the receipt of this order.

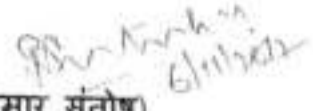


30

९.१. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

9.1. The appeals filed by the appellant stand disposed off in above terms.

सत्यापित,

प्रवीण पोपट
अधीक्षक (अपील्स)


(कुमार संतोष)
आयुक्त (अपील्स)

By Regd. Post AD

To,

M/s. Rankers International P. Ltd, "Ranker House", Plot No. 12, Sector No. 1, Gandhidham -Kutch	मे. रैंकर्स इंटरनेशनल प्रा. ली., "रैंकर हाउस", प्लॉट नं. 12, सेक्टर नं. 1, गांधीधाम - कच्छ
---	--

Copy to:

- 1) The Chief Commissioner, GST & Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad.
- 2) The Commissioner, GST & Central Excise, Kutch Commissionerate, Gandhidham
- 3) The Assistant Commissioner, GST & Central Excise Gandhidham Division, Gandhidham
- 4) Guard File.

✓ F.No 42/28/GDM/2017

